भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 466
गुरुवार, 28 नवंबर, 2024/7 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

हवाई अड्डों पर कार्बन तटस्थता

466. श्री थरानिवेंथन एम.एस.:
श्री मलैयारासन डी.:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा तमिलनाडु सहित देश भर के हवाई अड्डों पर कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) हवाई अड्डे के संचालन में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या पहल और प्रौद्योगिकि यां लागू की जा रही हैं;

(ग) कि तने हवाई अड्डे कार्बन तटस्थता स्थाति प्राप्त कर चुके हैं या इस दिशा में काम कर रहे हैं;

(घ) देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) क्या निजी कंपनियों को हवाई अड्डों पर टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कोई प्रोत्साहन या साझेदारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ङ): नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने अनुसूचित परिचालनों वाले सभी कार्यशील हवाईअड्डों और आगामी ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकासकर्ताओं को कार्बन न्यूट्रैलिटी एवं नेट जीरो प्राप्त करने की दिशा में काम करने की सलाह दी है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ हरित ऊर्जा का उपयोग भी शामिल है।

नागर विमानन मंत्रालय ने देश के हवाईअड्डों पर कार्बन न्यूट्रलिटि की दिशा में काम करने के लिए पहल की है और भारतीय हवाईअड्डों के कार्बन अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग ढांचे को मानकीकृत करने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन शमन पर जागरूकता पैदा करने के लिए ज्ञान साझा करने हेतु सत्र आयोजित किए हैं। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित परिचालनों वाले हवाईअड्डा प्रचालकों को अपने-अपने हवाईअड्डों पर कार्बन उत्सर्जन का खाका तैयार करने और चरणबद्ध तरीके से कार्बन न्यूट्रलिटि एवं नेट जीरो उत्सर्जन की दिशा में काम करने की सलाह दी गई है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) सहित हवाईअड्डा प्रचालकों ने हवाईअड्डों पर हरित ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए हरित एवं नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन और स्व-उपभोग के लिए विभिन्न स्थानों/हवाईअड्डों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ हवाईअड्डे ऑपन एक्सेस के माध्यम से भी हरित ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। अन्य पहलों में ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुसार भवन डिजाइन को अपनाना, पारंपरिक वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना, ऊर्जा दक्ष हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी), लाइटिंग और बैगेज हैंडलिंग सिस्टम आदि शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत नागर विमानन मंत्रालय ने एयरस्पेस के लचीले उपयोग (एफयूए) की अवधारणा को पूर्ण रूप से लागू करके राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र का इष्टतम उपयोग करने का सुझाव दिया है। इससे सभी रिपोर्टिंग एयरलाइनों को उड़ान समय और ईंधन उपयोग में महत्वपूर्ण बचत के माध्यम से लगभग 868.1 करोड़ रुपये की संचयी बचत हुई है और 01 अगस्त, 2020 से सीओ2 उत्सर्जन में 188538.5 टन से अधिक की संचयी कमी भी आई है।

वर्ष 2014 से, तमिलनाडु राज्य में चेन्नै, कोयंबटूर, त्रिची, मदुरै और तूतीकोरिन हवाईअड्डों सहित कुल 80 हवाईअड्डों ने 100% हरित ऊर्जा उपयोग को अपना लिया है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे हवाईअड्डों ने लेवल 4+ और उच्चतर हवाईअड्डा अंतर्राष्ट्रीय परिषद (एसीआई) मान्यता प्राप्त कर ली है तथा वे कार्बन न्यूट्रल बन गए हैं।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए), प्रमुख हवाईअड्डों की टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया के दौरान हरित ऊर्जा परियोजनाओं, कार्बन न्यूट्रलिटि आदि से संबंधित पूँजीगत व्यय को ध्यान में रखता है।

*****